DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Shri H.D. Devegowda — Not present. Dr. Radha Mohan Das Agrawal.

Need to investigate high death rate of tribal children in the tribal region 'Attapadi' in Palakkad district of Kerala

श्री राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, केरल के जिले पालक्काड़ में एक आदिवासी बहुल ब्लॉक अट्टपाड़ी है। पिछले दस वर्षों से वहां बच्चों की मृत्यु दर केरल ही नहीं वरन देश की औसत दर से भी अधिक है। केरल बहुत कम मृत्यु दर के लिए राजा बलि के जमाने से पूरी दुनिया में विख्यात है। आज उसी केरल के आदिवासी क्षेत्र में न जाने किन कारणों से दसियों वर्षों से बच्चों की बहुत अधिक मौतें हो रही हैं। भारत सरकार ने अपनी ओर से विशेष प्रयास किया और 120 करोड़ रुपये की विशेष मदद की। इसे मिलाकर राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपये खर्च किये। तीन फैमिली हैल्थ सेंटर्स, 28 सब-सेंटर्स, पांच मोबाइल यूनिट और एक सुपर-स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल होने के बावजूद मौतों का सिलसिला अनवरत जारी है। 30 योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी 50 परसेंट औरतें कुपोषित हैं। आंगनवाड़ी नॉन-फंक्शनिंग है और कम्युनिटी किचन्स बंद पड़े हैं। सारी स्कीमों का पैसा और व्यवस्था कहां जाती है, पता नहीं चलता। गर्भवती महिलाएं अट्टपाड़ी से पालघाट और पालघाट से त्रिशूर के बीच घूमती हैं। अट्टपाड़ी के नागरिकों की फूड हेबिट में जबरन परिवर्तन भी इसका कारण बताया जाता है। इन परिस्थितियों में अट्टपाड़ी में केन्द्र सरकार की ओर से बाल रोग विशेषज्ञों, स्पेशल साइंटिस्ट्स, फूड न्यूट्रिशनिस्ट्स आदिवासी समाज के प्रणेताओं का एक विशेष दल तीनों जनजातियों की भाषा विशेषज्ञों के साथ भेजा जाना आवश्यक है। ...(व्यवधान)...

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I am on a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री राधा मोहन दास अग्रवाल: टीम में बॉयोकेमिस्ट तथा हेमेटोलॉजिस्ट और उनकी टीम भी होनी चाहिए। बच्चों की अत्यधिक मृत्यु का कारण पता किया जाना बहुत आवश्यक है।

DR. JOHN BRITTAS: Sir, today morning you gave a ruling that whatever Member says has to be substantiated. ...*(Interruptions)*... Now, I am asking the hon. Member to substantiate this. ...*(Interruptions)*...

श्री राधा मोहन दास अग्रवाल: अन्यथा अट्टपाड़ी केरल और भारत में सामाजिक व्यवस्था पर एक प्रश्नचिह्न बना रहेगा, धन्यवाद।

DR. JOHN BRITTAS: Now, I am asking the hon. Member to substantiate this. ...*(Interruptions)*...

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

Need for increased allocation of funds for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme is supposed to provide 100 days of employment to the rural poor in India. But, the scheme is affected by increasing wage arrears and the workers are forced to seek work elsewhere. The skyrocketing inflation along with unemployment has put the rural poor under extreme distress. The rural unemployment continues to remain high.

In this context, the Government should take pro-active steps to ensure that the allocation of MGNREGS is immediately increased so that 100 days of employment can be ensured. There are several complaints about wages not being paid on time,